स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था परखने आज से मैदान में उतरेंगे अधिकारी

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था परखने के लिए मुख्यालय के अधिकारी आज से मैदान में उतरेंगे। मतलब अधिकारी जिलों में पहुंचकर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और शैक्षणिक व्यवस्था की जानकारी लेंगे। प्रत्येक अधिकारी को 8 बिंदुओं की जानकारी अपने दो दिन के निरीक्षण में जुटाकर प्रमुख अधिकारियों के पास जमा करनी होगी। जबलपुर जिले में राज्य शिक्षा केन्द्र की सीमा सक्सेना दो दिन तक स्कूलों का दौरा करेंगी। हालांकि जिले की प्रभारी अधिकारी सीमा सक्सेना किस तारीख को शहर पहुंचेगी यह भी तय नहीं किया गया है।

राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक आईरीन सिंथिया जेपी ने जबलपुर सहित 51 जिलों के प्राथमिक-माध्यमिक स्कूलों का भ्रमण करने के लिए कार्यालय के 51 अधिकारियों को मैदान में उतारने की तैयारी की है। सभी अधिकारियों को जिलों का प्रभार बांटते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक ने 22 से 27 जुलाई तक शैक्षणिक व्यवस्थाओं की जानकारी एकत्रित कर 1 अगस्त को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दो दिन का निरीक्षण कार्यक्रम

- प्रभारी अधिकारी को निरीक्षण के दौरान दो प्राथमिक, दो माध्यमिक शालाओं में पहुंचकर व्यवस्थाएं देखनी होगी।
- शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विकासखंड और जिलेस्तर पर प्रभारी अधिकारी समीक्षा करेंगे।
- दो दिन के निरीक्षण के बाद प्रभारी अधिकारी को 3 दिनों में जिला भ्रमण की रिपोर्ट मुख्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

इन बिंदुओं की समीक्षा होगी

- बच्चों के नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव की समीक्षा।
- हितग्राही मूलक योजना (पाठय पुस्तक, गणवेश, साइकिल, छात्रवृत्ति आदि) की समीक्षा।
- शिक्षक दैनिदिंनी का संधारण एवं कक्षा शिक्षण का निरीक्षण।
- 10-10 अंकों के मासिक पाठयक्रम पर आधारित प्रश्नपत्र की समीक्षा।
- जिलास्तरीय अकादमिक गुणवत्ता योजना निर्माण की स्थिति की समीक्षा।
- वर्ष 2018-19 में हुए एंडलाइन टेस्ट के आधार पर समूह निर्माण एवं दक्षता उन्नयन की स्थिति।
- स्कूलों में आकाशीय बिजली एवं बज्रपात, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के किए गए प्रयास की समीक्षा।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत सत्र 2019-20 के लिए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाओं में प्रवेश की समीक्षा होगी।

प्राथमिक-माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा तय की गई प्रभारी अधिकारी सीमा सक्सेना करेंगी। अभी तय नहीं हुआ है कि प्रभारी अधिकारी किस दिन शहर पहुंचेगी।

-**अजय दुबे**, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारी को देना होगा चयनित शालाओं पर ध्यान

धार : अधिकारी गोद लेंगे 222 सरकारी स्कूल, तीन माह में बनाएंगे मॉडल

धार। नईदुनिया प्रतिनिधि

जिले की 222 प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं को अब सरकारी अधिकारी गोद लेकर 3 महीने में उनकी दशा सुधारने की कोशिश करेंगे। इस दिशा में प्रयास शुरू हो चुका है। कलेक्टर से लेकर मैदानी स्तर के अधिकारी प्रत्येक संकुल स्तर पर एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेकर उसको मॉडल के तौर पर विकसित करेंगे। सबसे पहले भौतिक संसाधन के तौर पर शालाओं की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक गुणवत्ता विशेष ध्यान देंगे।

इस तरह का प्रयोग कमिश्नर इंदौर आकाश त्रिपाठी के निर्देश पर किया जा रहा है। धार जिले की 222 शालाएं चयनित की गई हैं, जहां पर पहले से ही भौतिक संसाधन व अन्य मामले में

111

संकुल से 1-1 प्राथमिक व माध्य. शाला का किया गया है चयन

बेहतर स्थिति है। आदेश के पालन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक संकुल स्तर पर एक माध्यमिक और एक प्राथमिक शाला ऐसी चयनित की जाए, जो कि भौतिक संसाधन यानी भवन से लेकर फर्नीचर व अन्य स्तर पर सशक्त हो। इस तरह से वहां पर उन्हें आदर्श बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए अब जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी जाएगी। अब तक इस तरह का मामला शिक्षा विभाग या जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारी ही देखते आ रहे थे, लेकिन अब कलेक्टर से लेकर निचले स्तर पर सारे अधिकारी इस तरह से 222 शालाओं के मामले में विशेष रूप से काम करेंगे।

इसके अंतर्गत 3 महीने के लिए इन अधिकारियों को शालाओं को गोद लेना होगा। भौतिक संसाधनों की कमी दूर करने के बाद शैक्षणिक गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों की कमी दूर करने से लेकर वहां की पढ़ाई व्यवस्था को ठीक करने का भी काम किया जाएगा। अगस्त से यह कवायद शुरू हो जाएगी। 3 महीने में ब्लॉक स्तर के छोटे से छोटे अधिकारियों को गोद ली गई शालाओं का निरीक्षण करना होगा। वहां की व्यवस्थाएं ठीक करना होंगी। चाहे वह पीने के पानी का इंतजाम हो, भोजन हो या फिर अन्य कोई व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं में आदर्श रूप होना चाहिए। बच्चों को गणवेश से लेकर अन्य पाठ्य सामग्री सुविधाएं उपलब्ध हो रही हों, यह भी सुनिश्चित करना होगा। इसके पीछे मकसद है कि अधिकारी विशेष रूप से 1-1 शालाओं पर फोकस कर सकेंगे। इसके अलावा ये अधिकारी मैदानी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर काम कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में तो उसके लिए बुनियादी काम भी शुरू हो चुका है। अब केवल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इस मामले में हरी झंडी मिलना बाकी है।

जिला शिक्षा केंद्र के सहायक परियोजना समन्वयक भूषण देशपांडे ने बताया कि व्यवस्था के तहत अधिकारियों को मैदानी स्तर पर जो दिक्कत है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी रहेगी। कमीश्नर के निर्देश के तहत इस योजना पर काम किया जा रहा है। स्कूल चयनित हो गए हैं, जल्द ही मैदानी स्तर पर योजना क्रियान्वित होगी।

अफसर करेंगे विद्यादान, आर्थिक सहयोग की अपील

अफसरों की पत्नियां व इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी लेंगे क्लास

ग्वालियर। नईदुनिया प्रतिनिधि

सरकारी स्कूलों में विद्यादान योजना के तहत जहां आला अधिकारी बच्चों को पढ़ाने पहुंचेंगे। वहीं विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों से स्कूलों की दशा-दिशा सुधारने आर्थिक सहयोग की अपील की गई है। विद्यादान योजना के लिए जिले के 100 स्कूलों को प्राथमिक तौर पर चिन्हित किया गया है। बाद में अन्य स्कूलों चयन भी किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) संजीव शर्मा का कहना है कि न केवल जिले के आला अधिकारी, बल्कि उनकी पत्नियां व कॉलेजों के इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी विद्यादान के लिए सहभागिता निभाएंगे। इसके साथ ही कैट, चैंबर ऑफ कॉमर्स व दाल बाजार समेत अन्य व्यापारिक व सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपील है।

डीईओ का कहना है कि स्कूलों में केवल विद्या का दान ही नहीं, अपनी छमता अनुसार कोई भी किसी भी तरह से सहयोग प्रदान कर सकता है। जिसमें आर्थिक मदद के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता भी शामिल हो। सोमवार को होने वाली टीएल की बैठक में इस सबंध में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। एक दो दिन में कलेक्टर

इंजीनियर गणित व मेडीकल स्टूडेंट देंगे बायो का ज्ञान

डीईओ का कहना है कि विद्यादान अभियान सप्ताह-दो सप्ताह या महीनेभर नहीं, बल्कि पूरे सत्र जारी रहेगा। कक्षा 1 से 12 वीं तक विद्यार्थियों को कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी समेत अन्य अधिकारी पढ़ाएंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों पर विशेष फोकस रहेगा।

खास बात यह है कि आईआईआईटीएम, आईटीएम व अन्य कॉलेजों के इंटेलिजेंट विद्यार्थी बच्चों को पढ़ाने आएंगे। ऐसे में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों से गणित व मेडीकल विद्यार्थियों से बायोलॉजी का व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को मिल सकेगा। 9वीं के विद्यार्थी ऐसे होनहार बच्चों से पढ़कर उत्साहित होंगे व 12वीं में अपना विषय चुनन में उन्हे सहायता मिलेगी।

सहभागी बनने वॉट्सअप पर भेजे डीटेल, आप भी बने सहभागी

विद्यादान योजना में आप भी सहभागिता निभा सकते हैं और स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता समेत कुछ अन्य जानकारी देनी होगी। यह डीटेल्स प्रशासन द्वारा जारी किए गए वॉट्सएप नंबर-8865870275 पर भी भेज सकते हैं। डीटेल्स के लिए भी एक फॉर्मेट जारी किया गया है। जरूरी नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाएं ही। बल्कि किसी भी तरह का सहयोग स्कूलों के लिए कर सकते हैं।

चैंबर से बहुत विद्वान जुड़े हैं

सीए समेत विभिन्न उद्योग-व्यापारों में महारत प्राप्त बहुत से विद्वान चैंबर से जुड़े हुए हैं। उन सभी से हम अपील करेंगे कि विद्यादान योजना में सहभागी बनें। स्कूलों की दशा सुधारने के लिए हम यथासंभव आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

विजय गोयल
अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स, ग्वालियर

आर्थिक सहयोग भी करेंगे

विद्यादान सराहनीय कदम है, जिसमें कैट भी सहभागिता निभाएगा। हम बच्चों को पढ़ाने भी जाएंगे और आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। संगठन स्तर व व्यक्तिगत तौर पर जैसा व जितना भी सहयोग बनेगा, हमारे द्वारा किया जाएगा।

भूपेन्द्र जैन, प्रदेशाध्यक्ष, कैट

विद्यादान योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। वे उत्कृष्ट विद्यालय मुरार के विद्यार्थियों को पढ़ाने पहुंचेंगे।